राष्ट्रीय · National

नई चेतना 5.0 अभियान, खनिज नियमों में संशोधन व भारत-नेपाल ₹15,000 करोड़ सहायता समझौता

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लैंगिक समानता हेतु 'नई चेतना 5.0' अभियान की घोषणा की है। वहीं कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत नियमों में संशोधन किया तथा भारत ने नेपाल को ₹15,000 करोड़ की सहायता दी।

राष्ट्रीय · National

1. नई चेतना 5.0 अभियान

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2026 तक संचालन
- DAY-NRLM के तहत लैंगिक हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन
- 15 मंत्रालयों की भागीदारी व हिंसा-मुक्त गांव पहल पर एमओयू

राष्ट्रीय · National

2. खनिज रियायत नियम संशोधन 2026

- कोयला मंत्रालय ने अधिसूचित किए खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम
- APA व MPPA एजेंसियों की मान्यता वैधता 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई
- पुनर्मूल्यांकन का प्रशासनिक बोझ घटेगा, खनन योजनाओं में निरंतरता

राष्ट्रीय · National

3. भारत-नेपाल विकास समझौता

- नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह की पहली भारत राजकीय यात्रा संपन्न
- भारत द्वारा ₹15,000 करोड़ की द्विपक्षीय सहायता की ऐतिहासिक घोषणा
- ₹3,500 करोड़ बाढ़ पुनर्निर्माण अनुदान व ₹11,500 करोड़ ऊर्जा ऋण

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

नई चेतना 5.0 अभियान अवधि	25 नवंबर से 23 दिसंबर 2026
नोडल मिशन	दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM
खनन मान्यता वैधता विस्तार	3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष
मूल खनन अधिनियम	MMDR अधिनियम, 1957
नेपाल सहायता पैकेज	₹15,000 करोड़ (NPR 24,000 करोड़)
ऊर्जा क्षेत्र लाइन ऑफ क्रेडिट (नेपाल)	₹11,500 करोड़

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

राष्ट्रव्यापी लैंगिक अभियान 'नई चेतना - पहल बदलाव की' किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख पहल है?

A ग्रामीण विकास मंत्रालय

B महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

C सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

D गृह मंत्रालय

उत्तर / Answer: A — 'नई चेतना' अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत चलाया जाता है।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

कोयला मंत्रालय द्वारा खनिज रियायत नियमों में किए गए तीसरे संशोधन 2026 के अनुसार APA और MPPA एजेंसियों की मान्यता वैधता कितने वर्ष कर दी गई है?

A 4 वर्ष

B 5 वर्ष

C 6 वर्ष

D 7 वर्ष

उत्तर / Answer: B — संशोधित नियमों के तहत मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण और खनन योजना तैयार करने वाली एजेंसियों की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends